राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक खबरें

जनता की समस्या,हर पल टाइम्स की खबर

HAR PAL TIMES

# हर पल टाइम्स

RNI NO:- MAHHIN/2011/24374

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

● वर्ष : ०८ ● अंक : २२ ● मुंबई, शुक्रवार, १ फरवरी से ७ फरवरी २०१९ ● पृष्ठ : ४ ● मूल्य : २/- रुपये

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला

अखबार,(०७४९८५३५२८६आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करे)

## बिल्डरों ने दबा रखे हैं मुंबई के २ लाख फ्लैट

**मुंबई :** सभी मुंबईकरों की एक ख्वाहिश होती है कि काश मुंबई में अपना एक घर होता! पर हर किसी का नसीब जोरदार नहीं होता। मुंबई के १० फीसदी लोगों के पास अभी भी अपना घर नहीं है और उन्हें हर ११ महीने बाद किराए का घर बदलने के लिए यहां-वहां भटकना पड़ता है। दूसरी तरफ बिल्डरों ने मुंबई में २ लाख घर दबा रखे हैं। ये वे घर हैं जो बनकर खरीददारों की राह ताक रहे हैं। पर इन महंगे घरों के लिए खरीददार नहीं हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि कोई दर-दर, कहीं बेतहाशा घर! मुंबई क्षेत्र में करीब ३ लाख परिवार अभी भी किराए के घरों में रहते हैं।

दूसरी तरफ काफी महंगी कीमतों के कारण आम मध्यम वर्ग घर नहीं खरीद पा रहा है। सिर्फ मुंबई में इस समय २ लाख से भी ज्यादा घर अनबिके पड़े हुए हैं जबकि ३,४०,००० निवासी इकाई का निर्माणकार्य काफी धीमी गति से चल रहा है या फिर उनका काम बंद है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो ८ मेगा सिटी में करीब ७ लाख से भी ज्यादा घर अनबिके पड़े हुए हैं। इसमें पुणे में सवा लाख और बंगलुरु में एक लाख घर शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि मुंबई में २०१३ से २०१९ के बीच घरों की कीमतों में ७.५० फीसदी बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके पूर्व २००७ से २०१० तक प्रॉपर्टी का बूम जबरदस्त था। उस दौर में घरों की कीमतें ४ से ५ गुनी तक बढ़ी थी। इस कारण निवेशकों ने प्रॉपर्टी में बड़ी मात्रा में निवेश किया था। बिल्डरों ने भी कई नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इसके लिए बैंकों से कर्ज भी लिए गए। आज जबकि प्रॉपर्टी बाजार भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा है तो निवेशकों के साथ ही बैंकों के भी पैसे अटक गए हैं। रियल इस्टेट इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में ११,००० बिल्डरों ने बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से जो कर्ज लिए हैं वह करीब ४ लाख करोड़ है। जानकारों के अनुसार इस समय बाजार में घरों के बिकने का जो सिलसिला है उसके अनुसार अगर ये पैसे वापस किए जाएं तो पूरा पैसा वापस करने में ७ साल का वक्त लगेगा।

## आंदोलन करेगी पुलिस!

### भेद लेने के लिए भेष बदलेगी

**मुंबई :** अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करनेवाले आंदोलनकारियों के साथ अब मुंबई पुलिस भी आंदोलन करेगी। उग्र आंदोलनकारियों पर गुप्त रूप से नजर बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह नई पहल की है। इसकी शुरुआत आजाद मैदान से की जा रही। आंदोलनकारियों के बीच अब पुलिस के जवान उन्हीं के वेशभूषा में शामिल होकर उनका भेद जानने के लिए उनके आंदोलन में शामिल रहेगी।

बता दें कि आजाद मैदान आंदोलनकारियों के आंदोलन स्थल के रूप में चर्चित है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर राजनीतिज्ञ लोग सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आजाद मैदान में आंदोलन करते हैं। यहां आंदोलन करनेवाले संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को सरकारी आदेश मिलने के बाद सरकारी अफसरों से पुलिस सुरक्षा में मंत्रालय में मिला जाता है। बताया जाता है कि अक्सर आंदोलनकारी अपनी मांगें सरकार से मनवाने के लिए चोरी-छुपी रणनीति भी तैयार कर लेते हैं जिसकी भनक पुलिस को मिलने से पहलें उसे अंजाम दे बैठते हैं। ऐसे में इन उग्र आंदोलनकारियों की गुप्त रणनीति को भेदने के लिए अब पुलिस ने भी रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत अब पुलिस के जवान आंदोलनकारियों के बीच जाएंगे। पुलिस की इस नई रणनीति की भनक आंदोलनकारियों को न हो इसके लिए महिला और पुरुष पुलिस आंदोलनकारियों की वेशभूषा में उनके बीच रहकर आंदोलन करेंगे।

हर पल टाइम्स

### अपील

**२०१९ के आने वाले इलेक्शन पर रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत आम जनता को है। हम हिंदुस्तान की पूरी जनता से अपील करते हैं कि आप उस की सरकार बनाएं जो आपकी ये सब जरुरतें पूरी कर सकें और वोट जरूर दें।**

**-संपादक**

महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा प्रमाणित

१०वीं क्लास में फेल होने वाले और १०वीं के आगे कोई भी क्लास या ग्रेज्युएशन करने के लिए हमारे पास कई सुविधाएं हैं। हमसे संपर्क करे...

अली खान सर

९८७००७३१११

Ali Khan : 9870073111

Kalam Khan : 9022630224

7021291844

ENFANT INDIA SENIOR SECONDARY SCHOOL

Co-ordinator Maharashtra

Plot No.13 & 7, Shivaji Nagar, Govandi, Mumbai - 400 043.

: eies@enfantindia.org

## मुंबई गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में बड़ी लापरवाही

**२०१२ शे नए कनेक्शन लगाए गए तब से आज तक पानी नहीं आया ना ही एम वार्ड के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई की न ध्यान दिया सिर्फ पानी के बिल भेजे गए पानी नही मिलने पर बिल कैसे दिया जाएगा, लाईन को दुरुस्त करने का वादा किया गया था, पानी मिलने पर बिल मिलेगा**

**संवाददाता**

**मुंबई,** शिवाजी नगर, ब्लॉट नं. २५ इस इलाके में २०१३से नए नल कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन अफसोस की आज तक इन नलों में पानी नहीं आया, इसकी कई बार शिकायतें एम/ईस्ट वार्ड में की गई। लेकिन कोई पानी पर कार्रवाई न ऑफिसर देखने आए और पानी के बिल बार-बार भेजे जा रहे हैं, इस पूरे प्लॉट में सब लोग परेशान हैं, आखिर म्युनिसपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है?

इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और पानी न मिलने पर बिल न भेजा जाए और पैसा न मांगा जाए। पहले नलो में पानी भेजा जाए और बाद में बिल भेजें। हालांकि शिवाजी नगर के कई इलाकों में पानी बेफाम बर्बाद हो रहा है। म्युनिसपल कार्पोरेशन के कर्मचारियों की बिलकुल तवज्जो नहीं है। इस सारे मुश्किलों का जवाबदार कौन है? दूसरे बारिश सामने खड़ी है और घरों के पीछे गटरों में कचरा जमा हो जाता है और जो नीचे के मकानात हैं, उसमे पानी आ जाता है। जबकि बड़े पैमाने पर कार्पोरेशन में गटर के कॉंट्रेक्ट देकर सफाई का काम बताया जा रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। २०१२ शे नए कनेक्शन लगाए गए तब से आज तक पानी नहीं आया ना ही एम वार्ड के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई की न ध्यान दिया सिर्फ पानी के बिल भेजे गए पानी नही मिलने पर बिल कैसे दिया जाएगा, लाईन को दुरुस्त करने का वादा किया गया था, पानी मिलने पर बिल मिलेगा।

## संपादकीय...

# हंगामा और राजनीति

**कोलकाता में रविवार से जो हंगामा चल रहा है, उसमें सारदा और रोज वैली जैसी पोंजी योजनाओं के नाम पर हुए घोटालों की बात की जा रही है। देश की संघीय संरचना की बात भी की जा रही है। लोगों के लिए यह तय कर पाना भी मुश्किल हो गया है कि कौन बड़ा लोता है, केंद्र सरकार की सीबीआई, या पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य पुलिस? हालांकि यह भी सभी जानते हैं कि इस पूरी लड़ाई को कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाले अंदाज में ही देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस समय जो हो रहा है, उसे आगामी आम चुनाव से जोड़कर न देखा जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए वहां जो भी हो रहा है, उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाएंगे ही। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ सप्ताह से भाजपा और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच रार गहराती जा रही है। इस समय पश्चिम बंगाल कुछ उन राज्यों में से एक है, जिसके बारे में भाजपा को लगता है कि वहां एक बड़ी चुनावी जीत दर्ज करा सकती है। इसलिए उसने अपनी सक्रियता वहां तेजी से बढ़ाई है। दूसरी तरफ, ममता बनर्जी ने भी उसे कड़ी टक्कर देने की ठान रखी है। पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति नहीं दी गई। रविवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करने पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई।**

**उसी शाम को सीबीआई के ४० अधिकारी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर सारदा घोटाले के बारे में पूछताछ करने के लिए जा पहुंचे। हमें पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत न देना और सीबीआई अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के घर पहुंचना, दोनों जुड़े हुए मामले हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें इन्हें जोड़कर देखा जाना ही था। उसके बाद सीबीआई अधिकारियों को पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाया जाना। फिर कोलकाता के सीबीआई कार्यालय को पुलिस द्वारा घेर लिया जाना, यह सब ऐसा घटनाक्रम था, जिसने दोनों ही दलों को अपनी-अपनी राजनीति साधने का पर्याप्त कारण उपलब्ध करा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत धरने पर बैठ गईं। सारे विपक्षी दल उनके समर्थन में आ गए। भाजपा नेताओं के तरकश में भी बहुत से तीर आ गए। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में ममता बनर्जी पर हमले करने शुरू कर दिए। शायद भाजपा ने सोचा हो कि वह केंद्रीय बजट पर चर्चाओं से आम चुनाव के अभियान का श्रीगणेश करेगी, लेकिन चुनाव अभियान पश्चिम बंगाल से शुरू हो चुका है। अब जरा इस पूरी राजनीति को अलग परिस्थितियों में रखकर सोचिए। मान लीजिए, इस देश में पुलिस और प्रशासनिक सुधार लागू हो चुके होते, तो सूरत क्या होती? तब सीबीआई को तोता नहीं माना जाता, उसकी अपनी एक विश्वसनीयता होती और अगर वह पुलिस कमिश्नर के घर पूछताछ के लिए पहुंचती, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं तलाशे जाते। तब यह भी नहीं कहा जाता कि स्थानीय पुलिस जो कदम उठाए, उनके पीछे राज्य सरकार का दबाव था। यानी तब मंशा पर सवाल नहीं उठते और मामला वैसे आगे बढ़ता, जैसे उसे वास्तव में बढ़ना चाहिए। तब ऐसे घटनाक्रम से राजनीति के मुद्दे नहीं निकलते और दलों को वास्तविक मुद्दों की राजनीति पर मजबूर होना पड़ता।**

# 'मंदिर गई, अब सामाजिक छुआछूत की शिकार'

**नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमला मसले पर दायर की गई

पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मंदिर में प्रवेश करने वाली बिंदु और कनकदुर्गा की आवाज भी उठी और उनकी ओर से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने मार्मिक तकरीर पेश करते हुए कहा, 'इन्हें (दोनों महिलाओं को) सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मंदिर में दाखिल हुई थीं, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। इससे यह लगता है कि मासिक धर्म वाली महिलाएं अशुद्ध और प्रदूषित हैं। यह दुखद है।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने २८ सितंबर, २०१८ को अपने ऐतिहासिक फैसले में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमला मंदिर के पट हर उम्र की महिलाओं के लिए खोल दिए थे। इस आदेश के बाद कुल ६४ याचिकाएं कोर्ट के सामने आईं, जिनमें फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए ५६ याचिकाएं थीं।

इंदिरा जयसिंह ने कहा, 'बिंदु की मां को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये दोनों सामाजिक बहिष्कार की शिकार हैं। इन दोनों महिलाओं को छुआछूत का शिकार होना पड़ा है क्योंकि इनके प्रवेश के बाद मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। भगवान अयप्पा महिला औरर पुरुष में भेद नहीं करते। भगवान की नजर में कोई विभेद नहीं है।' इंदिरा जयसिंह समेत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस पर आदेश में सुनाया जाएगा। सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं का केरल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। राज्य की तरफ से कहा गया कि इनमें से किसी भी याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके बिना पर २८ सितंबर, २०१८ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत हो। केरल सरकार के वकील ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिव्यू का कोई आधार नहीं है। इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया है।' वहीं, विजय हंसारिया ने कहा कि रिव्यू अर्जी के जरिए दोबारा मामले को खोलने की कोशिश की जा रही है। एक तय उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करना हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। रिव्यू पिटिशन का हम विरोध करते हैं।

# कांग्रेस की जनसंघर्ष सभा

**मुंबई :** केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा गुरुवार से शुरू हो रही है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले पार्टी राज्य भर में ५० सभाएं करेगी। इसकी शुरुआत औरंगाबाद के दौलताबाद से होगी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अशोक चव्हाण ने दावा किया कि भाजपा सरकार के खिलाफ अबतक जितने भी आंदोलन किए गए, वे सभी सफल रहे। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अब तक साढ़े छह हजार किलोमीटर की यात्रा कर १२० विधानसभा क्षेत्रों में जनता से सीधे संवाद किया। आज गुरुवार को फिर सरकार के खिलाफ जनआंदोलन शुरू कर रहे हैं।

# मराठा कोटा सरकार का चुनावी हथकंडा है: कोर्ट

**मुंबई :** मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का जो निर्णय किया है वह राजनीतिक रुप से लिया गया है और यह सरकार का एक चुनावी हथकंडा है। उसका यह भी दावा है कि सरकार को यह निर्णय लेने की विधाई शक्ति नहीं है। न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाधीश भारती डांगरे ने बुधवार को इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं की अंतिम सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इन याचिकाओं में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में १६ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

वकील जी सदावर्ते ने याचिकाकर्ता जयश्री पाटील की ओर से पेश होते हुए कहा कि सरकार का निर्णय केवल चुनावी लाभ पाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून यह कहता है कि आरक्षण ५० प्रतिशत से

ज्यादा नहीं हो सकता है, जबकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शामिल करते हुए यह व्यवस्था ७८ प्रतिशत हो गई है। सरकार केंद्रीय कानून से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता।

उन्होंने यह भी कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मराठा समुदाय को एक जाति नहीं बताया है बल्कि कुन्बी जाति का हिस्सा बताया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया है। अब इस मुद्दे पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी।

# गवाह बनने को तैयार इंद्राणी मुखर्जी, कोर्ट करेगा सवाल

**मुंबईः** बहुचर्चित INX मीडिया केस में गुरुवार को एक बड़ा अपडेट आया. इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गवाह बनने की बात कही थी, आज कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण मुंबई की भायखला जेल से कनेक्ट होगी. यहां कोर्ट इंद्राणी मुखर्जी से पूछेगा कि क्या इसके लिए उन पर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया है.

आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी शीना वोरा मर्डर केस में सजा काट रही हैं. और पिछले ४ साल से जेल में ही बंद हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने बीते साल दिसंबर में कोर्ट को चिट्ठी लिख इस मामले में गवाह बनने की बात कही थी.

गौरतलब है कि आज ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करेगा. ईडी के अलावा कार्ति पर इस केस में सीबीआई का भी शिकंजा है.

आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने एँफ की प्राथमिकी के आधार पर एक PMLA का मामला दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि INX मीडिया को २००७ में ३०५ करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है, इस दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम थे.

ED व ED यह भी जांच कर रही हैं कि कैसे UPA सरकार में मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम एफआईपीबी की मंजूरी प्राप्त करने में कामयाब रहे. गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम को २८ फरवरी, २०१८ को गिरफ्तार किया गया था, बाद

में उन्हें जमानत मिल गई.

ED की अब तक की जांच से पता चला है कि इच्छुँ की मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के पीटर व इंद्राणी मुखर्जी ने पी.चिदंबरम से मुलाकात की थी, ताकि उनके आवेदन में किसी तरह की देरी न हो. ईडी ने कहा है कि इस तरह से जो रुपया संबंधित निकायों को मिला, वह गैरकानूनी रूप से एएससीपीएल में लगा दिया गया. ED ने कार्ति चिदंबरम की ५४ करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया है. ईडी ने इसी से जुड़े मामले में मुखर्जी की संपत्तियों को भी कुर्क किया है.

# अस्पताल की लापरवाही कफन हटा तो दंग रह गए घरवाले

**मीरा रोड :** घर में चारों तरफ गम का माहौल था। परिवार के लोग चीख-चिल्ला रहे थे। अर्थी सजाई जा रही थी। जब वक्त आया मुख दर्शन का और मुंह से कफन हटाया गया तो सब के सब अवाक रह गए क्योंकि वह लाश किसी और की थी। यह वाकया मीरा रोड-पूर्व के भक्ति वेदांत अस्पताल के परिचारक के लापरवाही से शेट्टी परिवार के साथ हुआ।

मीरा रोड निवासी शेट्टी ने अपने ७० वर्षीय पिता भुजंगा शेट्टी को तबीयत नाजुक होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां २५ जनवरी की सुबह ३.१५ बजे उन्होंने अंतिम सांसें लीं। अस्पताल के कागजी खानापूर्ति के बाद शव को ९.५० बजे उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शेट्टी के निधन की खबर सुनकर करीब १५० रिश्तेदार और सगे-संबंधी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर जमा हुए थे। भुजंगा

शेट्टी के पुत्र ने बताया कि जब उनकी मां के आग्रह पर मुख दर्शन के लिए मुंह पर से कफन हटाया तो वह शव उनके पिता का नहीं था। आक्रोशित शेट्टी परिवार ने फोन कर भक्ति वेदांत अस्पताल को इसकी जानकारी दी।

# नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

**मुंबई :** बोरीवली पुलिस ने 30 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। घटना रविवार शाम की है, जब आरोपी पीड़िता को घर से बाइक पर बिठाकर गोराई ले गया, जहां उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।


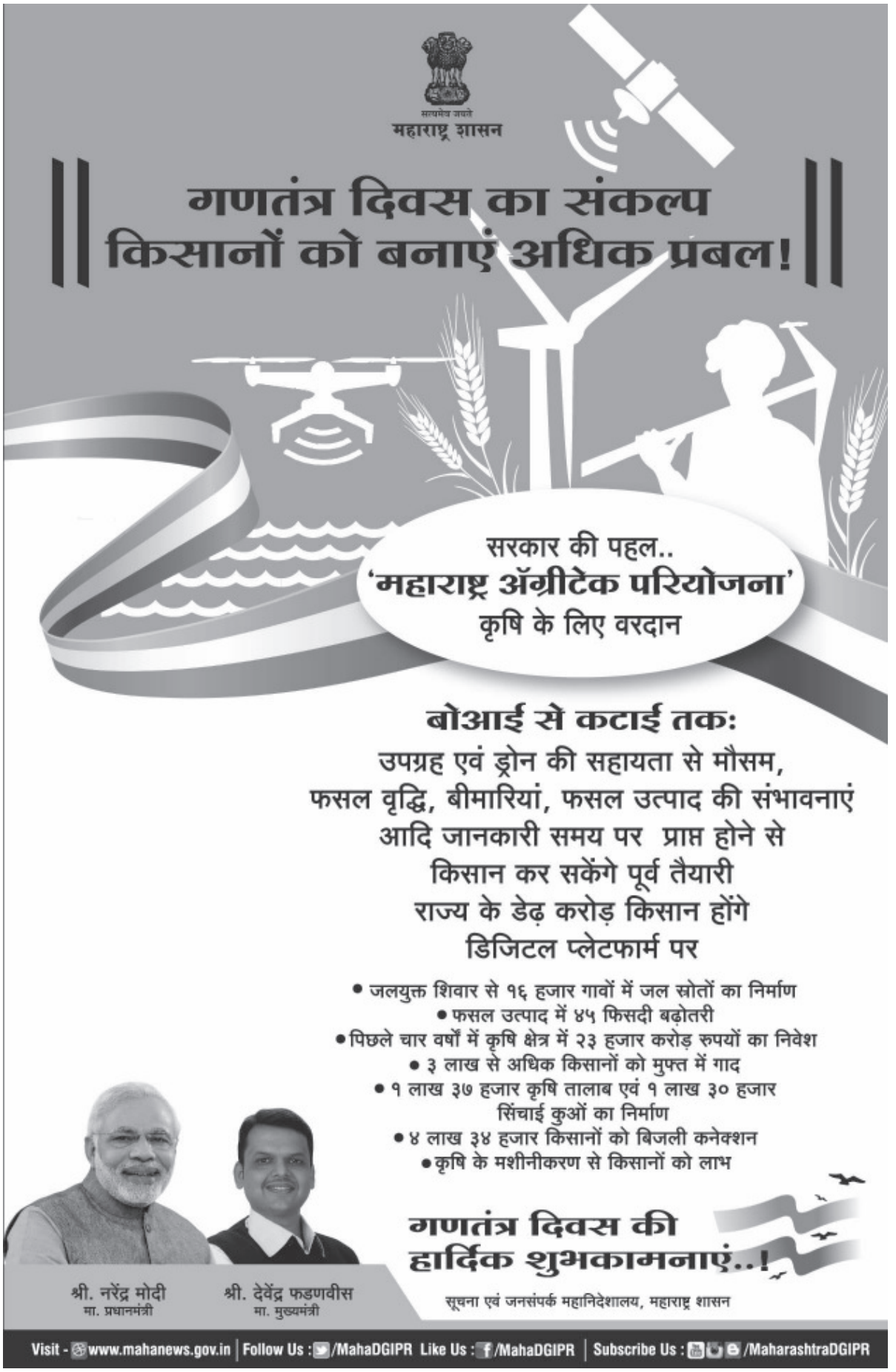

## संक्षिप्त न्यूज

### 'पुरानी आरक्षण व्यवस्था के लिए याचिका'

**नई दिल्ली:** मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पुरानी आरक्षण व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाने के बाद अब सरकार समीक्षा याचिका दायर करेगी। शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन के महेनजर सरकार ने यह घोषणा की है।

### जीसैट-३१ का इसरो ने किया सफल प्रक्षेपण

**बेंगलुरु :** देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-३१ को बुधवार तड़के फ्रेंच गुयाना से एक यूरोपीय रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन से एटीएम नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डीटीएच सेवा भी मजबूत होगी। उपग्रह की मिशन अवधि १५ साल है।

### 'शिवराज का हैलिकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं'

**कोलकाता :** भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने बुधवार को कहा कि जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के हैलिकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी है। इसी कारण मुर्शिदाबाद में होने वाली उनकी रैली को रद्द कर दी गई है। राज्य भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने बताया, 'शिवराज खड़गपुर में रैली में शामिल होंगे।'

### १९८४ कानपुर सिख दंगों की जांच होगी

**लखनऊ :** उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में १९८४ के सिख दंगों की जांच के लिए चार सदस्यों का विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व डीजीपी अतुल के नेतृत्व वाली एसआईटी को यह जांच सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित एसआईटी राज्य सरकार को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

### लौटती भीड़ को नहीं संभाल पाया प्रशासन

**प्रयागराज:** मौनी अमावस्या का स्नान करने के बाद अपने घरों को लौट रही भीड़ को जिला प्रशासन नहीं संभाल पाया, जिससे बुधवार को शहर के कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई। कई सड़कों पर वन-वे ट्रैफिक होने और रास्ते बंद होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ शहर के लोग भी घंटों जाम से जूझते रहे। सुबह से शुरू हुई यह स्थिति देर शाम तक बनी रही।

# सीबीआई और आरबीआई में घमासान

सीबीआई और आरबीआई दोनों में घमासान होने से यह पक्का हो गया है कि इस सरकार की पकड़ न आम लोगों की सुरक्षा पर है, न पैसे पर. अगर सीबीआई के सब से ऊंचे अफसर अपने से नीचे वालों को गिरफ्तार करने लगें और नीचे वाले खुद ऊपर वालों की शिकायतें करने लगें तो पक्का है कि सीबीआई यानी सैंट्रल ब्यूरो औफ इंटैलीजैंस की जगह सड़ा बैगन औफ इंडिया बन गया है. इसी तरह आरबीआई में रिजर्व बैंक औफ इंडिया की तरह काम नहीं कर रहा रुपया बरबादी इंजन बन गया है. सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे. नरेंद्र मोदी को तो मंदिरों में पूजा करने, विदेशों के दौरे करने, मूर्तियों के फीते काटने, भाषण देने, नेहरू खानदान पर दोष मढ़ने के अलावा कुछ और काम नहीं है. उन के पहले दायां हाथ रहे अरुण जेटली केवल कमरे में बैठ कर बोल सकते हैं क्योंकि वे बीमार ही चल रहे हैं. आरबीआई उन की सुनता नहीं है या समझता है कि वकील को भला फाइनैंस के मामलों का क्या पता. सीबीआई का काम राजनाथ सिंह के हाथों में होना चाहिए पर उन्हें भी और मंत्रियों की तरह देशभर में फालतू में हांफते देखा जा सकता है, देश का हिसाब रखते नहीं. सीबीआई का अंदरूनी झगड़ा डराने वाला है क्योंकि ऊपर के दोनों अफसरों ने एकदूसरे पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. उम्मीद यह की जाती रही है कि सीबीआई ही बेईमानों को पकड़ेगी पर पिछले ४ डायरैक्टरों पर तरहतरह के इलजाम लग चुके हैं. अब हालात ये हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दोनों ऊपरी अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है. जो नया अफसर सरकार ने बनाया है वह कोई फैसले नहीं ले सकता. सरकारी तोता अब पिंजरा तोड़ चुका है पर उस के पर तो सैकड़ों डोरों से बंधे हैं जो अपनी मनमरजी का काम कराते रहे हैं. साफ है कि जितने छापे सीबीआई ने पिछले ४ सालों में मारे हैं सारे सरकार ने बदले की भावना और विपक्षियों की टांग तोड़ने के लिए मरवाए हैं और सीबीआई ने बढ़चढ़ कर फायदा उठाया है. अब जनता जनार्दन यह नहीं कह सकती कि पुलिस या सरकार गलत है तो सीबीआई से जांच कर लो. वे दिन हवा हो गए जब सीबीआई पर भरोसा था. अमेरिकी फिल्मों में अकसर एफबीआई और एनआईए (फैडरल ब्यूरो औफ इनवैस्टीगेशन और नैशनल इंटैलीजैंस एजेंसी) की ज्यादतियों के सीन दिखाए जाते हैं जबकि यहां सीबीआई को साफसुथरा, कर्मठ, मेहनती, देशप्रेमी ही दिखाया जाता रहा है. अब कलई उतर गई है. सोने की परत के नीचे पीतल का नहीं कच्ची मिट्टी का बरतन है जिस में जो चाहे जहां मरजी छेद कर ले. आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का झगड़ा सामने आया है क्योंकि दोनों को अब नरेंद्र मोदी की पकड़ पर भरोसा नहीं रह गया है. सरकार ने जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना कर सत्ता कुछ हाथों में समेट ली थी, उन हाथों के काले कारनामे इन दोनों अफसरों के पास मौजूद हैं. इन का चाहे तो भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए छुट्टी पर जाने के आदेशों के बावजूद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत दिखाई. यह सरकार राज करना भूल चुकी है. इसे तो यज्ञहवन करना ही आता है.

# मोदी सरकार की देन है सीबीआई का संकट

उच्च ओहदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जो मोदी और अमित शाह के विवादास्पद इतिहास को मिटाने के काम में शामिल हैं और सीबीआई में हाल के तख्तापलट के बाद इन नियुक्तियों पर सवाल उठाया जाना चाहिए. सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना को रातोरात हटाए जाने और इस संस्थान के राजनीतिकरण के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है. इस तख्तापलट पर जारी कानूनी उठापटक में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं. अभी हाल में सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मनीष सिन्हा ने खुलासा किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य लोगों ने अस्थाना के खिलाफ जांच में दखल दिया था. सीबीआई के अक्सर राजनीतिक प्रभाव में आकर काम करने की बात को स्वीकारते हुए २०१३ में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे का तोता कहा था. लेकिन फिलहाल जो चल रहा है, वैसा विवाद सार्वजनिक रूप में शायद ही अब से पहले देखने को मिला है. मीडिया में प्रकाशित सीबीआई के निदेशक की जासूसी करने वाले चार अधिकारियों को गिरफ्तार करते सुरक्षाकर्मियों की फोटो, संस्थान में आई अभूतपूर्व गिरावट को दर्शाता है. इस विवाद के केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के पिछले कामों का साया है- दागदार छवि वाले उनके चहते अधिकारी, नौकरशाह और कानूनी अधिकारियों को दिल्ली के बड़े ओहदो पर रखा गया है. मोदी और अस्थाना का रिश्ता उस वक्त से है जब अस्थाना ने २००२ में गोधरा रेलवे स्टेशन में जलाई गई रेल की छानबीन की थी. उस हादसे में मारे गए ५९ लोगों में ज्यादातर कारसेवक थे. अस्थाना ने पड़ताल के नतीजे में कहा था कि रेल को मुस्लिम भीड़ ने सुनियोजित षडयंत्र के तहत जलाया था. परिणामस्वरूप मार्च २०११ में आए एक फैसले में ३१ लोगों को दोषी करार दिया गया.

**हरपल टाईम्स व हरपल टीवी न्यूज**

क्राईम द मोस्ट वांटेड व क्राईम इंन्वेस्टिगेशन न्यूज देश के सभी जगहों पर हमारी खास न्यूज बतायी जा रही है अगर आपको, मोबाईल और लेपटॉप, पर देखनी हो तो www.harpaltvnews.com टाइप करके देखिये या crimeinvestigationharpaltv.com टाईप करके सभी खबरें देख सकते हैं, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारा नंबर है ७४९८५३५२८६ अगर आपको खबर भेजना है तो ईमेल करें : Email-harpaltimes.press@gmail.com

**कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है..**
संपर्क करें : ७०२१४२५४४२

मालक, मुद्रक, प्रकाशक वसीम जे. खान ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल.कॅम्प, चेंबूर, मुंबई -४०००८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५ डी/१. शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई - ४०००४३ से प्रकाशित किया। संपादक: वसीम जे. खान. RNI NO:- MAHHIN/2011/24374 .
Email--harpaltimes.press@gmail.com 074985 35286 (सभी विवाद निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र मुंबई,महाराष्ट्र होगा।)